

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्श,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 2

देहरादून : दिनांक : 14 जनवरी, 2009

विषय: नवनिर्मित जिला न्यायालय भवन, रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर) के चहारदीवारी के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2008-2009 में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 67-दो(8)/XXXVI(1)(2)/2007-08-50-दो(8)/07, दिनांक 18.3.2008 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि नवनिर्मित जिला न्यायालय भवन, रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर) के चहारदीवारी के निर्माण हेतु रु० 59,93,000/- के आगणन के मापेश टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित रु० 58,00,000/- (अन्दाधुन लाख रुपये मात्र) की रकम के आगणन के विरुद्ध स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि रु० 38,78,000/- (अर्द्धतास लाख अट्ठत्त हजार रुपये मात्र) को वित्तीय वर्ष 2008-2009 में व्यय किये जाने की महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों का, जो दर सिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा । तदुपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी ।
- (2) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय तथा उच्च अधिकारियों के निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण रिपोर्टों के अनुरूप कार्य किया जाय ।
- (3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितनी राशि स्वीकृत की गयी है ।
- (4) एक मुश्त प्राविधानों का कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन आगणन प्राप्त कर लिया जाय ।
- (5) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित किया जाय ।
- (6) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों से कार्य स्थल का भली-भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय ।
- (7) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद का राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।
- (8) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय ।

- (9) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रुल्स, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्चोरमेंट) नियमावली, 2008 एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गतिवृत्ति एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेंसी/अधिशाली अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे ।
- (10) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006), दिनांक 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।
- (11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2009 तक पूर्ण उपयोग कर स्विकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।
- 3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-04 के आयोजनागत पक्ष में लेखा-शीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051-निर्माण-03-न्यायिक कार्य हेतु भवनों का निर्माण-00-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा ।
- 4- यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-133P/XXVII(5)/08, दिनांक 13.1.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)
सचिव ।

संख्या-54-दो(8)/XXXVI(1)(2)/2008 50 दो(8)/त तददिनांक ।

प्रतिसिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय बिल्डिंग, भाजरा, देहरादून ।
- 2- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
- 3- जिला न्यायाधीश, ऊधमसिंहनगर ।
- 4- चरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/ऊधमसिंहनगर ।
- 5- अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंहनगर ।
- 6- नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन ।
- 7- एन०आई०सी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।